

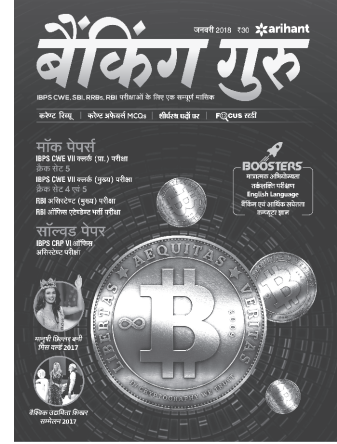
# इस माह

जनवरी 2018

वर्ष 3

अंक 12

वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन 2017 का आयोजन	02
15वें वित्त आयोग का गठन	03
ट्राई द्वारा नेट न्यूट्रिलिटी के पक्ष में सिफारिशें	04



## मॉक पेपर्स

IBPS क्लर्क (प्रा.) परीक्षा क्रैक सेट 4	39
IBPS क्लर्क (मुख्य) परीक्षा क्रैक सेट 1	46
क्रैक सेट 2	62
RBI ऑफिस अटेण्डेण्ट भर्ती परीक्षा	77
RBI असिस्टेण्ट (मुख्य) परीक्षा	86

## सॉल्वड पेपर

IBPS RRBs ऑफिस असिस्टेण्ट (प्रा.) परीक्षा 2017	97
--	----

## करेण्ट रिव्यू

बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था एनालिसिस	05
राष्ट्रीय अपडेट	09
अन्तर्राष्ट्रीय अप-टू-डे	15
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऑब्जर्वेशन	19
खेल-खिलाड़ी	23
चर्चा में....	28
पुरस्कार एवं सम्मान	32
वस्तुनिष्ठ करेण्ट अफेयर्स	35

## प्रैक्टिस Dossiers

मात्रात्मक अभियोग्यता • तर्कशक्ति परीक्षण English Language • कम्प्यूटर ज्ञान सामान्य एवं वित्तीय सचेतता • Descriptive English	104
---	-----

## बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था Q&A

शीर्षस्थ पदों पर	125
------------------	-----

सम्पादक : पायल जैन • चेयरमैन : वाईसी जैन • सह-सम्पादक राजेश राजन  
पब्लिशिंग मैनेजर महेन्द्र सिंह रावत • प्रोजेक्ट मैनेजर अमित त्यागी • न्यूज एडिटर संजय सागर  
कॉपी डेस्क आरके बहल • प्रूफ रीडर जगदीश नेगी • कवर एवं लेआउट बिलाल हाशमी  
मुख्य पेज डिजाइनर प्रदीप कुमार • टाइप सेटिंग नितिन कुमार

### वितरण एवं विज्ञापन

जनरल मैनेजर अनिल कुमार गुप्ता (9258074262) • ई मेल arihantmedia.ad@gmail.com  
सेल्स एक्जीक्यूटिव आशीष सिंह (उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान), सुशील राय (बिहार, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़)

### कार्यालय

प्रधान कार्यालय अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स कालिन्दी, टीपी नगर, मेरठ • फोन 0121-2401479, 2512970  
फैक्स 0121-2401648 • ई मेल bankingguru2015@gmail.com • वेबसाइट www.arihantbooks.com  
वितरण/व्यावसायिक कार्यालय अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स 457715, अग्रवाल रोड दरियागंज, नई दिल्ली-2  
फोन 011-47630600 • सब्सक्रिप्शन +91-9219641347 subscribe4arihant@gmail.com • इन्क्वायरी 0121-4030840

### © प्रकाशक

अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स के लिए श्रीमती पायल जैन द्वारा प्रकाशित एवं अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड, मेरठ से मुद्रित  
इस पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख उनके रचनाकारों के स्वयं के हैं, तथा वे किसी भी स्थिति में उनसे सम्बन्धित सरकारी या गैर-सरकारी संस्था या बैंकिंग गुरु सम्पादक मण्डल के विचार नहीं हैं।  
इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया है तो प्रकाशक,  
सम्पादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।  
किसी भी स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मेरठ (उत्तर प्रदेश) होगा।

# 15वें वित्त आयोग का गठन



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। 1 दिसम्बर, 2017 को पूर्व राजस्व सचिव एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी की है। जिन चार सदस्यों की नियुक्ति 15वें वित्त आयोग में की गई है, वे हैं

1. शक्तिकान्त दास — पूर्व सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग
2. अनूप सिंह — प्रोफेसर, जॉर्जटाउन युनिवर्सिटी
3. अशोक लाहिड़ी — चेयरपर्सन, बन्धन बैंक
4. रमेश चन्द — सदस्य, नीति आयोग

## संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280(1) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्षों की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इस परम्परा तथा संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रख कर प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व अगले वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

भारत में अब तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल, 2015 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें देने के लिए 2 जनवरी, 2013 को किया गया था।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध है। संवैधानिक प्रावधानों के नियमों के अनुसार 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह वित्त आयोग 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक के वित्त वर्ष के लिए सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा।

## 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी थे। इस आयोग ने केन्द्र तथा राज्य के राजकोषीय सम्बन्धों को पुनर्परिभाषित किया है। आयोग ने राज्यों के संयुक्त हिस्सेदारी को 32% से

बढ़ाकर 42% कर दिया है। यह देश के राजकोषीय ढाँचे में एक नवीन प्रयोग है।

- 14वें वित्त आयोग ने माना है कि राज्यों को संसाधनों के हस्तान्तरण के लिए कर अवमूल्यन का मार्ग अपनाना चाहिए।
- राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनागत तथा गैर-योजनागत विभाजन को समाप्त किया जाना जरूरी है।
- आयोग के अनुसार करों के विभाजन कारी प्रवृत्तियों को समाप्त करने से हस्तान्तरण की प्रक्रिया को गम्भीरतापूर्ण बनाया जा सकता है।
- आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 90% तथा क्षेत्रफल के आधार पर 10% अधिभार के साथ स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया।
- राज्यों को प्राप्त अनुदानों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए—पहला, पूर्ण रूप ग्राम पंचायतों की स्थापना वाले राज्य तथा दूसरा पूर्ण रूप से शहरी निकायों की स्थापना वाले राज्य।
- ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों को बेसिक अनुदान के साथ प्रदर्शन के आधार पर अधिक अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।
- बेसिक तथा प्रदर्शन के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का अनुपात 90 : 10 हो, जबकि शहरी निकायों के लिए यह अनुपात 80 : 20 हो।
- 14वें वित्त आयोग द्वारा कुल अनुदान ₹287436 करोड़ (पाँच वर्ष की अवधि) निर्धारित किया गया है जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए ₹200292 तथा शेष राशि नगर निकायों के लिए निर्धारित की गई है।

## 15वें वित्त आयोग की चुनौतियाँ

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020-25 के लिए होगी। केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करना एक कठिन प्रक्रिया है, किन्तु अब चुनौतियाँ और अधिक हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद वित्त आयोग को अपने सुझाव में ऋण तथा भुगतान स्तरों के साथ जीएसटी के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखना होगा।

15वें वित्त आयोग के सामने प्रदर्शन को मापने का नया पैमाना तैयार करने की चुनौती होगी। इसमें जनसंख्या वृद्धि तथा अन्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

## एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष

एनके सिंह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं। वह बिहार से राज्यसभा के प्रतिनिधि रहे हैं। वे संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य भी रहे हैं। एक प्रशासक के रूप में एनके सिंह ने शीर्षस्थ पदों पर कार्य किया है। वे राजस्व सचिव तथा पीएमओ में सचिव भी रहे हैं। एनके सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एनके सिंह ने 'पॉलिटिक्स ऑफ चेंज' तथा 'नॉट वाई रीजन एलोन' जैसी चर्चित पुस्तकों की रचना की है। वह विभिन्न मुद्दों पर समाचार-पत्रों में आलेख लिखते हैं।

# पुरस्कार एवं सम्मान



## राष्ट्रीय दिव्यांग जन अधिकारिता पुरस्कार

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने 3 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकारिता पुरस्कार-2017' वितरण किया।

अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस (3 दिसम्बर,) के अवसर पर प्रदान किए गए 'राष्ट्रीय दिव्यांग जन अधिकारिता पुरस्कार 2017' विभिन्न 14 श्रेणियों में दिए गए हैं। ये हैं

1. सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी एवं नियोजित दिव्यांग — कोई नहीं
2. (क) सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता — आईबीएम इण्डिया  
(ख) सर्वश्रेष्ठ नियोजन अधिकारी — यूथ फॉर जॉब्स
3. (क) सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत — टीएस चन्द्रशेखर  
(ख) दिव्यांग संस्थानों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था — ईटीसी एजुकेशन
4. प्रेरणा स्रोत — उसके कुमार/टी. बरार/अपूर्व ओम तथा अन्य
5. दिव्यांग जनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य — बालाजी वी तथा अन्य से सर्वश्रेष्ठ नवाचार
6. बाधा रहित वातावरण में उत्कृष्ट कार्य — जबलपुर जिला अधिकारी
7. पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला — मदुरई (तमिलनाडु)

8. सर्वश्रेष्ठ राज्य कार्यदायी संस्था — कोई नहीं
9. सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक बाल दिव्यांग — ओम जिग्नेस व्यास/अभिरामीर आर
10. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस — नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइण्ड (भारत)
11. सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक गुण सम्पन्न वयस्क दिव्यांग — गोपाल चन्द्रपाल/सुनीता टी एन
12. सर्वश्रेष्ठ पहुँच वाली वेबसाइट — जलगाँव पीपुल कॉर्पोरेटिव बैंक
13. दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य — छत्तीसगढ़
14. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी — शेखन नायक/सोनलबेन मनुभाई पटेल

## 48वाँ आईएफएफआई का हुआ समापन

48वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) का आयोजन 20 से 28 नवम्बर, 2017 के बीच पणजी (गोवा) में किया गया। समारोह के अन्त में 48वें आईएफएफआई अवार्ड्स का वितरण किया गया। फ्रांसीसी निर्देशक रोबिन केम्पिलो की फिल्म '120 बिट्स पर मिनट' को 'सर्वश्रेष्ठ फिल्म' का स्वर्ण मयूर अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष के 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म व्यक्तित्व' का अवार्ड दिया गया।

48वें आईएफएफआई अवार्ड्स की सूची निम्न है

श्रेणी	विजेता
श्रेष्ठ फिल्म	120 बिट्स पर मिनट (रॉबिन केम्पिलो)
श्रेष्ठ निर्देशक	विवियन क्यू (एंगेल्स बियर ह्वाइट)
श्रेष्ठ अभिनेता	नाहुएल पेरेज विसकायार्ट (120 बिट्स पर मिनट)
श्रेष्ठ अभिनेत्री	पार्वती थिरुवथू कोट्टूवता (टेक ऑफ)
लाइफटाइम अचीवमेण्ट	एटॉम एगान
इण्डियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर	अमिताभ बच्चन
बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर	किरो रूसो (डार्कस्कल)
युनेस्को गाँधी मेडल	क्षितिज-ए हॉरिजन
स्पेशल ज्यूरि अवार्ड	महेश नारायण (टेक ऑफ)

## आईसीसीआर इण्डोलॉजी अवार्ड 2017

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने 27 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रपति भवन में जापान के प्राध्यापक हिरोशी मारुई को तीसरा आईसीसीआर इण्डोलॉजी अवार्ड प्रदान किया। उन्हें 'भारत' के सन्दर्भ में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से जुड़ी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

हिरोशी मारुई विगत 40 वर्षों से भारतीय दर्शन और बौद्ध अध्ययन पर कार्य कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उनके शोध-पत्रों को अन्तिम जानकारी मानकर स्वीकार किया जाता है।

'जापानी एसोसिएशन ऑफ इण्डियन एण्ड बौद्ध स्टडीज' के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जापान में इण्डोलॉजी को बढ़ावा दिया है।

भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद (आईसीसीआर) द्वारा प्रत्येक वर्ष आईसीसीआर इण्डोलॉजी अवार्ड दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकों को 'भारत' से सम्बन्धित अध्ययन के लिए सम्मान के रूप में है।

# मॉक पेपर-1

ऑनलाइन परीक्षा 21 जनवरी, 2018

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान

# IBPS क्लर्क

मुख्य (फेज-II) परीक्षा 2017

## ● सामान्य निर्देश

- (i) दिया गया क्रेक सेट अभ्यास हेतु है, ताकि परीक्षार्थी परीक्षा-हॉल में प्रश्नों को निश्चित समय-सीमा के भीतर त्वरित गति से हल कर सकें।  
(ii) इस क्रेक सेट में कुल 190 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी से आपको ज्यादा-से-ज्यादा प्रश्न हल करने हैं।

समयावधि 160 मिनट

पूर्णांक 200

भाग	विषय-सामग्री	कुल प्रश्न	निर्धारित समय
1	सामान्य/वित्तीय सचेतता	50	३५ मिनट
2	अंग्रेजी भाषा	40	३५ मिनट
3	तर्कशक्ति एवं कम्प्यूटर अभियोग्यता	50	४५ मिनट
4	संख्यात्मक योग्यता	50	४५ मिनट

## ⊙ भाग 1 सामान्य/वित्तीय सचेतता

'प्लैण्ड इकोनॉमी फॉर इण्डिया' नामक पुस्तक किसने लिखी?

- a. एम. विश्वेश्वरैया    b. निर्मला सीतारमण    c. रघुराम राजन  
d. उर्जित पटेल    e. इनमें से कोई नहीं

निम्न में से किस पर सरकार द्वारा 'काउण्टरवेलिंग ड्यूटी' लगाई जाती है?

- a. उद्योग पर    b. विदेश से आयातित वस्तुओं पर  
c. विदेश निर्यात वस्तुओं पर    d. रियल एस्टेट पर  
e. इनमें से कोई नहीं

'स्वच्छ सर्वेक्षण 2017' में केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा देश के किस शहर को सबसे स्वच्छ (साफ-सुथरा) शहर के रूप में माना गया है।

- a. चण्डीगढ़    b. गंगटोक    c. इन्दौर    d. अहमदाबाद    e. लखनऊ

विश्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं?

- a. पूँजी की व्यवस्था  
b. पूँजी विनियोग को प्रोत्साहन  
c. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलित विकास  
d. ऋण प्रदान करना  
e. उपरोक्त सभी

विश्व के पहले पुलिस रोबोट का दुबई में अनावरण किया गया है। इस रोबोट पुलिस का क्या नाम है?

- a. रोबोकॉप    b. टर्मिनेटर    c. रोबोकवीक  
d. केवल 1 एवं 3    e. इनमें से कोई नहीं

नासा द्वारा खोजी गई किस चीज की प्रजाति को क्या नाम दिया है?

- a. बिटक्वाइन    b. कलाम    c. सीवी रमन  
d. B486    e. HEPA

'बट सीरियसली' पुस्तक के लेखक कौन हैं?

- a. जेके रॉलिंग    b. अबा के जिनमो    c. लुंग सुन की  
d. जॉन मैकनरो    e. इनमें से कोई नहीं

विम्बलडन चैम्पियनशिप 2017 में पुरुष एकल विजेता की ट्रॉफी रोजर फेडरर ने किस हराकर जीती?

- a. मारिन किलिक    b. राफेल नडाल    c. एण्डी मरे  
d. नोवाक जोकोविच    e. स्टेनिस्लास वावरिका

भारत, यूएसए, जापान की त्रिपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहते हैं?

- a. मिशन एशिया    b. पोसीडॉन    c. मालाबार  
d. सूर्यशस्त्र    e. IAJ17

सरकार व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का संयुक्त स्वामित्व कहलाता है

- a. लिमिटेड कम्पनी    b. मिक्सड कम्पनी    c. संयुक्त क्षेत्र  
d. ज्वॉइण्ट स्टोक    e. ये सभी

'गोल्ड कॉलर जॉब' में कौन-से वर्ग के लोग आते हैं?

- a. श्रमिक वर्ग  
b. उपभोक्ता वर्ग  
c. उच्चतम स्तर पर निर्णय-प्रक्रिया से सम्बन्धित वर्ग  
d. सामान्य वर्ग  
e. उपरोक्त में से कोई नहीं

जब सरकार का कुल विनियोग, कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो इसे क्या कहेंगे?

- a. विदेशी ऋण    b. विदेशी सहायता    c. फिडयूसियरी इश्यू  
d. वित्तीय घाटा    e. इनमें से कोई नहीं

# बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था

## Q&A

01

### राजकोषीय नीति क्या है ?

निर्देशात्मक आयोजन प्रणाली में राजकोषीय नीति की विकास के उपकरण के रूप में अत्यधिक निर्भरता होती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक सेवाएँ एवं सार्वजनिक निवेश आते हैं का सृजन करती है तथा उसे बनाए रखती है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों के पुनः आबण्टन, पुनर्वितरण, निजी बचतों तथा निवेशों के प्रोत्साहन एवं स्थिरता बनाए रखने का उपकरण है। अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सुधार तथा सामान्य लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना इस नीति का प्रमुख तथा उल्लेखनीय लक्ष्य है। राजकोषीय नीति किसी भी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि निष्पत्ति को दो प्रकारों से प्रभावित करती है। पहला, यह विकास के साधनों के एकत्रण को प्रभावित कर संवृद्धि निष्पत्ति पर प्रभाव डालती है तथा दूसरा यह साधनों के आबण्टन की कार्य-कुशलता में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।

02

### 'गैर-विकास व्यय' किसे कहते हैं ?

आर्थिक संवृद्धि से सम्बन्ध नहीं रखने वाले मदों में किया गया खर्च 'गैर-विकास व्यय' कहलाता है। आयोजन काल के 65 वर्षों में भारत में 'गैर-विकास व्यय' में कमी आई है, किन्तु निरपेक्ष रूप से इसमें वृद्धि हुई है। गैर-विकास व्यय प्रशासनिक दृष्टि से वांछनीय है। जनसंख्या वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ इसमें बढ़ोतरी होती है। 'गैर-विकास व्यय' को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। स्थिर कीमतों पर गैर-विकास व्यय में कुछ वृद्धि होना उचित है, किन्तु इसका अधिक तीव्र रूप से बढ़ना अव्यावहारिक है। प्रतिरक्षा, ब्याज के भुगतान, पुलिस और कर एकत्रण पर सर्वाधिक गैर-विकास व्यय का हिस्सा आता है। भारत में प्रतिरक्षा, ब्याज के भुगतान, पुलिस और कर एकत्रण पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कुल 16% हिस्सा खर्च होता है। इन पर होने वाले खर्च से अधिक इनकी कार्य-कुशलता पर ध्यान देना अनिवार्य माना जाता है।

03

### भारत में 'आयात प्रतिस्थापन नीति' पर टिप्पणी कीजिए।

आर्थिक आयोजन के आरम्भिक दशकों में भारत में अत्यधिक अन्तर्मुख व्यापार युक्ति को अपनाया जाता है। इसे अपनाने के पीछे तर्क यह था कि इससे आयात प्रतिस्थापन द्वारा तेजी से औद्योगिकीकरण हो सकेगा तथा विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह युक्ति काफी हद तक इन उद्देश्यों को पाने में सफल हो सकी है, किन्तु अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 'बाह्य-उन्मुख युक्ति' से अधिक लाभ होता है। अन्तर्मुख युक्ति अपनाते देशों में विकास अवरुद्ध हुआ है।

'विश्व बैंक' का भी मानना है कि बाह्य उन्मुख नीतियों से संसाधनों का अधिक बेहतर प्रयोग सक्षमता के साथ किया जाता है। अन्तर्मुख नीतियों से घरेलू संरक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि बाह्य उन्मुख नीतियों से उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धा आती है।

अन्तर्मुख युक्ति में उच्च प्रभावी संरक्षण दरें होती हैं। मुद्रा की दरें अवास्तविक रूप से बढ़ जाती हैं तथा निर्यात हतोत्साहित होता है।

04

### 'लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना' क्या है ?

खाद्य सहायता के बढ़ते भार को कम करने के उद्देश्य तथा उसे जरूरतमन्द लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना (टीपीडीएस) की शुरुआत की।

इस योजना के अधीन राज्यों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने को कहा गया। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के ऐसे परिवारों को इस योजना में रखने की व्यवस्था की गई, जिनकी आय उस समय ₹ 15000 वार्षिक से कम थी। आरम्भ में प्रति परिवार 10 किग्रा खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 25 किग्रा प्रतिमाह कर दिया गया। 1 अप्रैल, 2002 को राशन की मात्रा 35 किग्रा प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया।

05

### मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई) क्या है ?

ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट (एचडीआर) 1997 ने मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई) को पहली बार स्पष्ट किया था। यह सूचकांक मनुष्य के विभिन्न अभावों का मिला-जुला सूचकांक है। इसके अनुसार, मानव गरीबी का अनुमान किसी विशिष्ट मापक द्वारा पाना सम्भव नहीं है। मानव गरीबी की अवधारणा में स्वतन्त्रता तथा निर्णयों में भागीदारी का अभाव और व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी जैसी बातें भी आती हैं।

इस सूचकांक में मानव जीवन के तीन अभावों को केन्द्रित किया गया है। ये हैं

- जीवन, लम्बी अवधि का होना
- शिक्षा का अभाव
- अच्छे जीवन स्तर का न होना

मानव गरीबी सूचकांक तैयार करने के लिए एचडीआई 2007-08 में इन तीन अभावों को परिमाणत्मक रूप में प्रस्तुत किया गया।

06

### 'गरीबी अन्तराल सूचकांक' क्या है ?

'गरीबी अन्तराल सूचकांक' को गरीबी की रेखा के नीचे और दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। औसत, सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए लिया जाता है, इस कार्य के लिए जो लोग गरीब नहीं हैं, उनका 'गरीबी अन्तराल सूचकांक' शून्य माना जाता है।